OPEN ACCESS

Int. Jr. of Contemp. Res. in Multi. *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 4 Issue 5 [Sep- Oct] Year 2025*

Research Article

अंबाला जिले में एमपीएलएडी योजना के अंतर्गत सांसदों द्वारा निधि उपयोग: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Vaneeta Rani [1*], Dr. Mahinder Singh [2], Dr. Deepak [3]

[1] Scholar, Deptt. of Political Science, NIILM University, Kaithal, Haryana, India

[2] Associate Professor, Department of Political Science, NIILM University, Kaithal, Haryana, India

[3] Assistant Professor, NIILM University, Kaithal, Haryana, India

Corresponding Author: * Vaneeta Rani

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17499844

संदर्भ

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) की स्थापना भारत में 1993 में सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सशक्त बनाने हेतु की गई थी। इस शोधपत्र में एमपीएलएडी योजना से संबंधित आंकड़े हरियाणा के अंबाला जिले में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 के आधार पर प्रस्तुत और विश्लेषित किए गए हैं, जिसमें अनुशंसित, स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में व्यय पर ध्यान केंद्रित किया गया है। परियोजना कार्यान्वयन में रुझानों और पैटर्न की जांच के लिए आधिकारिक सरकारी रिपोर्टों और एमपीएलएडीएस दिशानिर्देशों के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। निष्कर्षों से पता चलता है कि 6 सालों की अवधि में अनुशंसित और स्वीकृत कार्यों की संख्या में उतार-चढ़ाव देखा गया है। हालाँकि, परियोजना पूर्णता दर और व्यय में उतार-चढ़ाव कार्यान्वयन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और निगरानी तंत्र को बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर करता है। श्रेणीवार विश्लेषण हाशिए पर रहने वाले समुदायों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने और संसाधनों के समान वितरण को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करता है। यह आलेख एमपीलैड पहलों की प्रभावशीलता में सुधार हेतु सुझावों के साथ समाप्त होता है, जिनमें प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और संसाधन असमानताओं को दूर करने के उपाय शामिल हैं। इस योजना का प्रभावी ढंग से लाभ उठाकर, सांसद सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने और राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 01-08-2025
- **Accepted:** 25-9-2025
- **Published:** 31-10-2025
- **IJCRM:**4(5); 2025: 532-540
- **©2025, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

Rani V, Singh M, Deepak. अंबाला जिले में एमपीएलएडी योजना के अंतर्गत सांसदों द्वारा निधि उपयोग: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. Int J Contemp Res Multidiscip. 2025: 4(5):532-540।

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द: एमपीलैड योजना, विश्लेषण, निधि उपयोग, स्थानीय विकास, सामाजिक आर्थिक प्रगति।

© 2025 Vaneeta Rani, Dr. Mahinder Singh, Dr. Deepak. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे भारत में 1993 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सांसदों (सांसदों) को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल, सड़क, रास्ते, बिजली और शिक्षा जैसी स्थानीय विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सशक्त बनाना है। इस योजना की परिकल्पना विकास योजना को विकेंद्रीकृत करने और सांसदों को अपने-अपने क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में सीधे योगदान करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने के साधन के रूप में की गई थी। (एमपीएलएडीएस, 2023) मंत्रालय ने अब एमपीलैड्स पर संशोधित दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं और नई निधि प्रवाह प्रक्रिया के लिए एक संशोधित प्रक्रिया 01.04.2023 से अपनाई जानी है। सांसदों के स्वीकृत कार्यों के अनुसार, अनुसूचित जाति के आवास वाले क्षेत्रों पर 22.5 प्रतिशत व्यय अनिवार्य है। एक वित्तीय वर्ष में ट्रस्ट/सोसायटियों के लिए 50 लाख रुपये और दिव्यांगजन कल्याण कार्यों के लिए 10 लाख रुपये की अनुमति है।(ग्रा.वि.वि. हरियाणा) अंबाला जिला हरियाणा राज्य के ऐतिहासिक प्रसिद्ध जिलों में से एक होने का दावा करता है। अंबाला में चार उप-विभाग हैं, अंबाला शहर, अंबाला कैंट, बरारा और नारायणगढ़, जिसमें चार तहसीलें (अंबाला शहर, अंबाला कैंट, बरारा और नारायणगढ़) और तीन उप-तहसीलें (शहजादपुर, मुलाना, साहा) शामिल हैं। अंबाला जिला हरियाणा के उत्तर-पूर्वी छोर पर 27-39″-45′ उत्तरी अक्षांश और 74-33″-53′ से 76-36″-52′ पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। (Ambala, GoH, India) इस शोध पत्र में हरियाणा के अंबाला जिले में सांसदों द्वारा एमपीएलएडीएस निधि के आबंटन और उपयोग का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अनुशंसित, स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में व्यय पर ध्यान केंद्रित किया गया है और एमपीएलएडी योजना से संबंधित आंकड़े हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 के आधार पर प्रस्तुत और विश्लेषित किए गए हैं।

2. अंबाला जिले का कुल क्षेत्रफल और जनसंख्या - 2011 की जनगणना के अनुसार अंबाला जिले का कुल क्षेत्रफल तालिका संख्या 1 में दी गई है।

तालिका 1: अंबाला जिले का कुल क्षेत्रफल

जिला	जिला/तहसील	क्षेत्रफल
अंबाला	अंबाला छावनी	1574.00
	अंबाला शहर	736.00
	बराड़ा	357.00
	नारायणगढ	481.06

स्रोतः निदेशक जनगणना कार्य, हरियाणा अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग हरियाणा

2.1. 2011 की जनगणना के अनुसार अंबाला जिले का कुल जनसंख्या तालिका संख्या 2 में दी गई है।

तालिका 2: POPULATION OF AMBALA

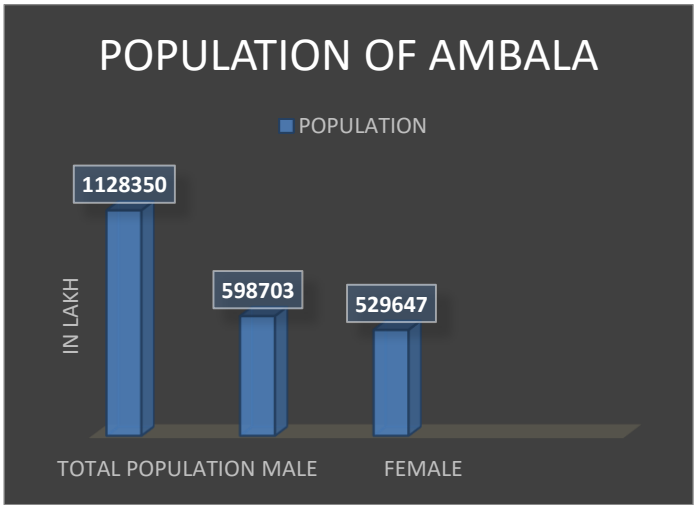

स्रोतः सांख्यिकीय सारांश हरियाणा 2023-24, अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा, 2025

2.1.2. 2011 की जनगणना के अनुसार अंबाला जिले का कुल क्षेत्रफल 1574.00 वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार अंबाला जिले की कुल जनसंख्या 11,28,350 है और जिसमें कुल पुरुष जनसंख्या 5,98,703 और महिला जनसंख्या 5,29,647 है।(सांख्यिकीय सारांश, 2023-24)

तालिका 3: POPULATION

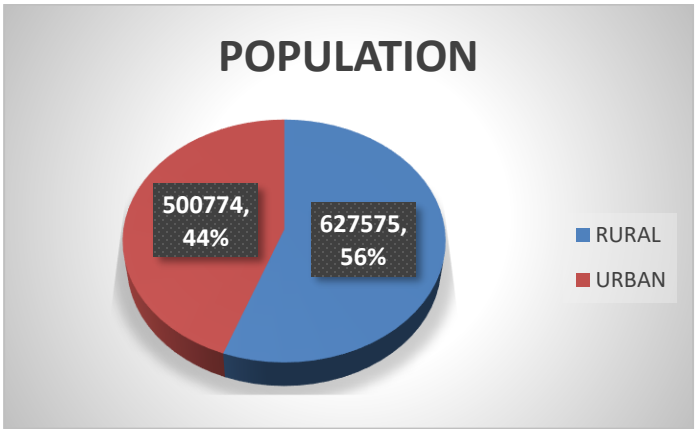

स्रोतः सांख्यिकीय सारांश हरियाणा 2023-24, अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा, 2025

अंबाला जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या 627575 और शहरी जनसंख्या 500774 हैं (सांख्यिकीय सारांश, 2023-24)

3. विधानमंडल

2011 की जनगणना के अनुसार, अंबाला जिले में 4 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और 1 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं जबकि एक निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से अंबाला जिले के अंतर्गत आता हैं। अंबाला जिले में 2011

© 2025 Vaneeta Rani, Dr. Mahinder Singh, Dr. Deepak. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

तक 1 नगर निगम, 2 नगर पालिकाएँ, 00 नगर पंचायतें, 461 ग्राम पंचायतें है।(सांख्यिकीय सारांश, 2023-24)

4. प्रस्तावित आंकडे और शोधकर्ता का विश्लेषण

इस अध्याय में हरियाणा के अंबाला जिले में सांसदों द्वारा एमपीएलएडीएस निधि के आबंटन और उपयोग का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अनुशंसित, स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में व्यय पर ध्यान केंद्रित किया गया है और एमपीएलएडी योजना से संबंधित आंकड़े हरियाणा में अंबाला जिले के वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 के आधार पर प्रस्तुत और विश्लेषित किए गए हैं

5. कार्यों की संख्या: हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान अंबाला जिले के अनुशंसित, स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या (MPPADS, GOH)

तालिका-4: अनुशंसित, स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों की कुल संख्या का विवरण

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	अनुशंसित कार्यों की कुल संख्या	स्वीकृत किए गए कार्यों की कुल संख्या	पूर्ण किए गए कार्यों की कुल संख्या
1	2014–2015	123	–	–
2	2015–2016	170	167	167
3	2016–2017	168	93	88
4	2017–2018	147	111	104
5	2018–2019	108	71	54
6	2019–2020	03	03	02
कुल जोड		**719**	**445**	**415**

Source*:* https://mplads.gov.in/mplads/Default.aspx

5.1 तालिका 4, वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के अंतर्गत अनुशंसित, स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों की कुल संख्या का विवरण प्रदान करती है। तालिका 4 के अनुसार अनुशंसित कार्यों की कुल संख्या में 6 वर्षों की अवधि में लगातार उतार चढाव देखा गया है, जो 2014-15 में 123 से घटकर 2018-19 में 108 हो गया। यह स्थानीय विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में एमपीएलएडीएस परियोजनाओं के महत्व की घटती मान्यता का संकेत देता है। परन्तु 2019-2020 के वर्ष में कोविड के कारण अनुशंसित कार्यों में 03 के साथ गिरावट देखी गई।

- इसी प्रकार, स्वीकृत कार्यों की कुल संख्या में भी उतार चढाव देखा गया है, जो सिफारिशों को अनुमोदित परियोजनाओं में बदलने की प्रतिबद्धता को नही दर्शाता है। हालाँकि, वृद्धि की दर अनुशंसित कार्यों की तुलना में कम प्रतीत होती है।
- दूसरी ओर, पूर्ण हुए कार्यों की संख्या में कार्यों में उतार चढाव के साथ एक सुसंगत पैटर्न दिखाई देता है। जो सिफारिशों को अनुमोदित परियोजनाओं में बदलने की प्रतिबद्धता को नही दर्शाता है। हालाँकि, वृद्धि की दर अनुशंसित कार्यों की तुलना में कम प्रतीत होती है। लेकिन पूर्णता दर पर्याप्त बनी हुई है, जो परियोजना कार्यान्वयन में प्रगति का संकेत देती है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुशंसित कार्यों की संख्या सबसे अधिक (168) देखी गई, जो उस अवधि के दौरान स्थानीय विकासात्मक चुनौतियों के समाधान पर गहन ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।
- 2018-19 तक सिफारिशों में वृद्धि और पूर्ण हुए कार्यों की संख्या में उल्लेखनीय रूप से उतार चढाव देखा गया हैं जो परियोजना निष्पादन में और कार्यान्वयन में उतार चढाव का संकेत देती है। परन्तु 2019-2020 के वर्ष में कोविड के कारण अनुशंसित कार्यों में 03 और पूर्ण हुए कार्यों में 02 के साथ गिरावट देखी गई
- वर्ष 2015-16 स्वीकृत कार्यों (167) की उच्चतम संख्या के साथ उल्लेखनीय रूप से उल्लेखनीय है, जो अनुशंसित परियोजनाओं के लिए धन को मंजूरी देने और आवंटित करने के लिए एक ठोस प्रयास को दर्शाता है।
- वर्षों की अवधि में, एमपीएलएडीएस के अंतर्गत कुल 719 कार्यों की अनुशंसा की गई, 445 कार्यों को स्वीकृत किया गया और 415 कार्य पूरे किए गए। ये आँकड़े इस योजना के माध्यम से स्थानीय विकासात्मक पहलों के लिए किए गए महत्वपूर्ण निवेश और प्रयासों को रेखांकित करते हैं।

5.2 कार्यों की लागतः हरियाण में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान अनुशंसित, स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों की लागत

तलिका 5: अनुशंसित, स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों की लागत

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	अनुशंसित कार्यों की लागत	स्वीकृत किए गए कार्यों की लागत	पूर्ण किए गए कार्यों की लागत
1	2014–2015	**3**	–	–
2	2015–2016	**8**	**6**	**6**
3	2016–2017	**9**	**5**	**4**
4	2017–2018	**9**	**5**	**5**
5	2018–2019	**7**	**6**	**3**
6	2019–2020	–	–	–
कुल जोड		**36**	**22**	**18**

Source: https://mplads.gov.in/mplads/Default.aspx

© 2025 Vaneeta Rani, Dr. Mahinder Singh, Dr. Deepak. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

सारणी 5, हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत अनुशंसित, स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों की लागत प्रस्तुत करती है। यह तालिका प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कार्यों के लिए अनुशंसित लागत, नोडल प्राधिकरण द्वारा कार्यों के लिए स्वीकृत राशि और 2014-15 से 2019-20 तक की 6 वर्ष की अवधि में पूर्ण किए गए कार्यों पर करोड़ों रुपये में हुए व्यय का विवरण प्रदान करती है। आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित जानकारी सामने आती है

- अनुशंसित कार्यों की कुल लागत में पिछले 6 वर्षों के दौरान भिन्नताएँ देखी गई है, जो 2014-15 में 3 करोड़ रुपये से बढ़कर 2017-18 में 9 करोड़ रुपये हो गई। परन्तु 2018-19 में यह घट कर 7 करोड़ रुपये तक पहुच गई। और 2019-20 में कोविड के कारण घट कर 0 करोड़ रुपये तक पहुच गई।
- इसी प्रकार, स्वीकृत कार्यों की कुल लागत में भी कमी देखी गई है, हालाँकि अनुशंसित कार्यों की तुलना में यह दर थोड़ी कम है। व्यय 2014-15 में 0 करोड़ रुपये से बढ़कर 2018-19 में 6 करोड़ रुपये हो गया। परन्तु 2019-20 में कोविड के कारण घट कर 0 करोड़ रुपये तक पहुच गई।
- पूरे हो चुके कार्यों की लागत में 6 वर्षों के दौरान उतार चढाव देखा गया हैं। 2014-15 से 2018-19 तक कुल मिलाकर उतार चढाव की स्थिति रही है। 2015-16 में व्यय 6 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया, जो उस वर्ष परियोजना कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण निवेश का संकेत देता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में सभी श्रेणियों में संख्या में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई, जो एमपीएलएडी परियोजनाओं के कार्यान्वयन और ठोस परिणाम देने पर गहन ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।
- उल्लेखनीय रूप से, अनुशंसित कार्यों की लागत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों की लागत से अधिक रही, जो नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए आवंटित वित्तीय संसाधनों की मात्रा को दर्शाता है।
- 6 वर्षों की अवधि में, अनुशंसित कार्यों के लिए कुल 36 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, अनुशंसित कार्यों के लिए 22 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, और एमपीएलएडी के तहत पूर्ण किए गए कार्यों के लिए 18 करोड़ रुपये खर्च किए गए। ये आंकड़े हरियाणा में लोकसभा के कार्यकाल के दौरान अंबाला जिले में इस योजना के माध्यम से स्थानीय विकासात्मक पहलों के लिए किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश को रेखांकित करते हैं।

तालिका 6: Recommended Work in Ambala by Cost

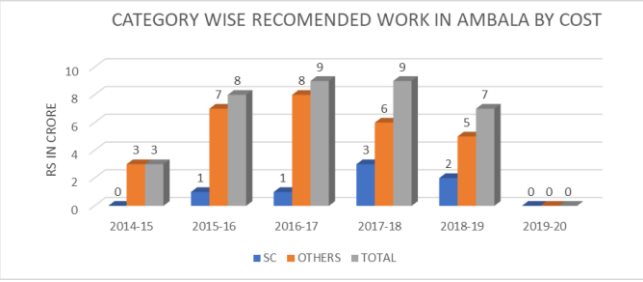

Source: https://mplads.gov.in/mplads/Default.aspx

6. हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान अंबाला जिले में अनुसूचित जाति और अन्य श्रेणियों के लिए अनुशंसित, स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों की लागत

6.1 विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुशंसित, स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों की लागत का वित्तीय वर्षवार विश्लेषण

6.1.1 वित्तीय वर्ष 2014-15

वित्तीय वर्ष 2014-15 के आंकड़े विभिन्न श्रेणियों में एमपीलैड योजना के तहत निधियों के वितरण और उपयोग को दर्शाते हैं। अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के अंतर्गत, 00 करोड़ रुपये की सिफारिश, स्वीकृत और पूर्ण किए गए। अन्य श्रेणी में सबसे अधिक 3 करोड़ रुपये की सिफारिश की गई, परन्तु 00 करोड़ रुपये स्वीकृत और उपयोग किए गए।

तालिका 6.1: WORK SANCTIONED BY COST IN AMBALA

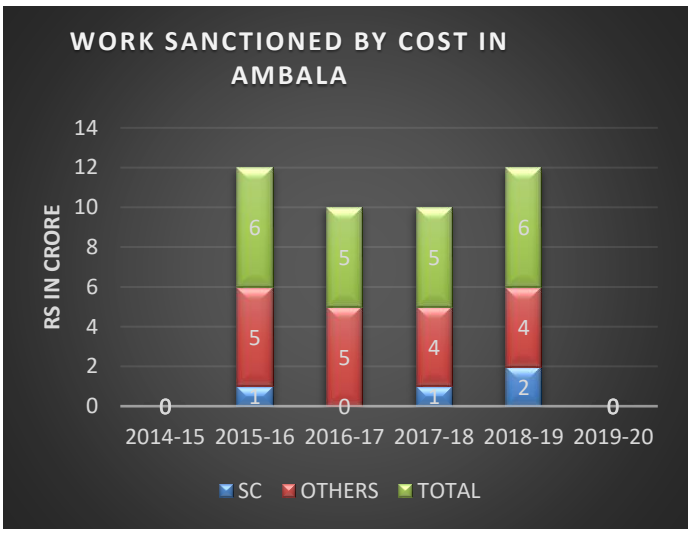

Source: https://mplads.gov.in/mplads/Default.aspx

6.1.2 वित्तीय वर्ष 2015-16

2015-16 के दौरान, अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी में 1 करोड़ रुपये की सिफारिश की गई, जिसमें 1 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए और 1 करोड़ रुपये पूरे हो चुके कार्यों पर खर्च किए गए। उल्लेखनीय रूप से, अन्य श्रेणी के लिए सबसे अधिक 7 करोड़ रुपये की अनुशंसा की गई, जिसमें 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए और 5 करोड़ रुपये उपयोग किए गए। सभी श्रेणियों के लिए कुल अनुशंसित राशि 8 करोड़ रुपये रही, जिसमें 6 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए और 6 करोड़ रुपये व्यय के रूप में थे।

6.1.3 वित्तीय वर्ष 2016-17

वित्तीय वर्ष 2016-17 में, अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के लिए 1 करोड़ रुपये के कार्यों की सिफारिश की गई, 00 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए और 0 करोड़ रुपये पूर्ण परियोजनाओं पर खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त, अन्य श्रेणी में 8 करोड़ रुपये की पर्याप्त अनुशंसित राशि देखी गई, जिसमें 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए और 4 करोड़ रुपये उपयोग किए गए। कुल मिलाकर, सभी श्रेणियों के लिए कुल

© 2025 Vaneeta Rani, Dr. Mahinder Singh, Dr. Deepak. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

अनुशंसित आवंटन 9 करोड़ रुपये था, जिसमें 5 करोड़ रुपये स्वीकृत और 4 करोड़ रुपये उपयोग किए गए।

तालिका 6.2: WORK COMPLETED BY COST IN AMBALA

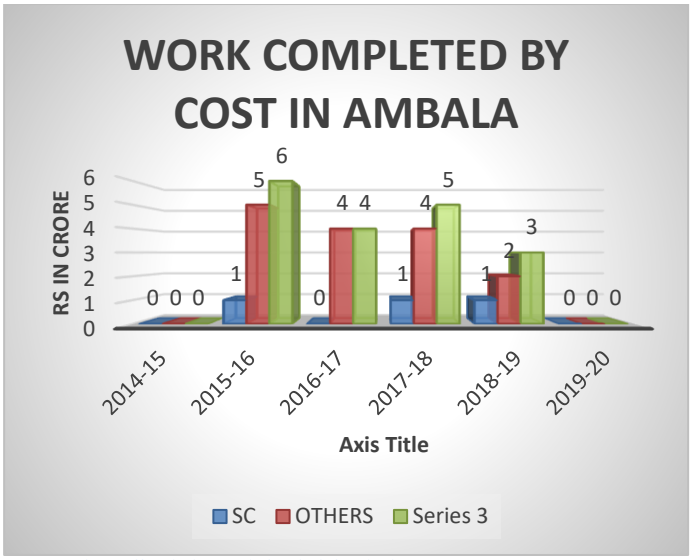

Source: https://mplads.gov.in/mplads/Default.aspx

6.1.4 वित्तीय वर्ष 2017-18

इस वित्तीय वर्ष में, अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के लिए 3 करोड़ रुपये की सिफारिशें की गईं, जिसमें 1 करोड़ रुपये स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपये व्यय किए गए। अन्य श्रेणी में महत्वपूर्ण सिफारिशें देखी गईं, कुल 6 करोड़ रुपये, जिसमें 4 करोड़ रुपये स्वीकृत और 4 करोड़ रुपये उपयोग किए गए। कुल मिलाकर, सभी श्रेणियों के लिए कुल अनुशंसित आवंटन 9 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 5 करोड़ रुपये स्वीकृत और 5 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

6.1.5 वित्तीय वर्ष 2018-19

वित्तीय वर्ष 2018-19 में, अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के लिए, सिफारिशें 2 करोड़ रुपयेकी थीं, जिसमें 2 करोड़ रुपये स्वीकृत और 1 करोड़ रुपये पूर्ण कार्यों के लिए उपयोग किए गए। उल्लेखनीय रूप से, अन्य श्रेणी में सबसे अधिक अनुशंसाएँ थीं, कुल 5 करोड़ रुपये, जिनमें से 4 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए और 2 करोड़ रुपये उपयोग किए गए। कुल मिलाकर, सभी श्रेणियों में कुल अनुशंसित आवंटन 7 करोड़ रुपये था, जिसमें 6 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए और 3 करोड़ रुपये पूर्ण परियोजनाओं पर व्यय किए गए।

6.1.6 वित्तीय वर्ष 2019-20

वित्तीय वर्ष 2019-20 में, अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी और अन्य श्रेणी के लिए, शून्य करोड़ रुपये की अनुशंसाए स्वीकृत और पूर्ण कार्यों के लिए उपयोग किए गए।

तालिका 7, 7.1 और 7.2 में हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान अनुसूचित जाति (एससी), और अन्य के आधार पर वर्गीकृत अनुशंसित, स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या प्रस्तुत की गई है। ये तालिकाएं निर्दिष्ट वित्तीय वर्षों में विभिन्न श्रेणियों में एमपीलैड योजना के तहत कार्यों की प्रगति और वितरण का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। हरियाणा में अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन के आंकडे उपलब्ध नही हैं (डच्स्।क्ैएडवैच्प्एळव्प्)

तालिका 7: WORK RECOMMENDED BY THE COUNT IN AMBALA

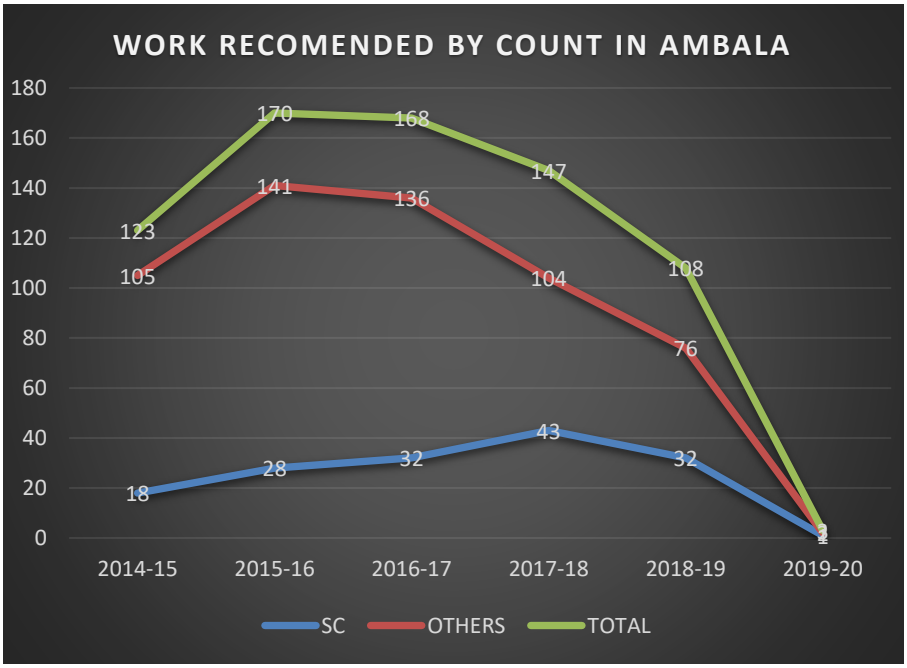

Source: https://mplads.gov.in/mplads/Default.aspx

© 2025 Vaneeta Rani, Dr. Mahinder Singh, Dr. Deepak. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

7.1 **अनुशंसित, स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों का विश्लेषण**
अनुशंसित कार्य - सभी श्रेणियों और वित्तीय वर्षों में, अनुशंसित कार्यों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जो विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव में संसद सदस्यों (सांसदों) की भागीदारी को दर्शाती है। अनुशंसित कार्यों की कुल संख्या 2014-15 में 123 से घट्कर 2018-19 में 108 हो गई,जो स्थानीय विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा ना करने की ओर संकेत है। और 2019-20 में कोविड के कारण यह घट कर 03 तक पहुच गई।

तालिका 7.1: WORK SANCTIONED BY COUNT IN AMBALA

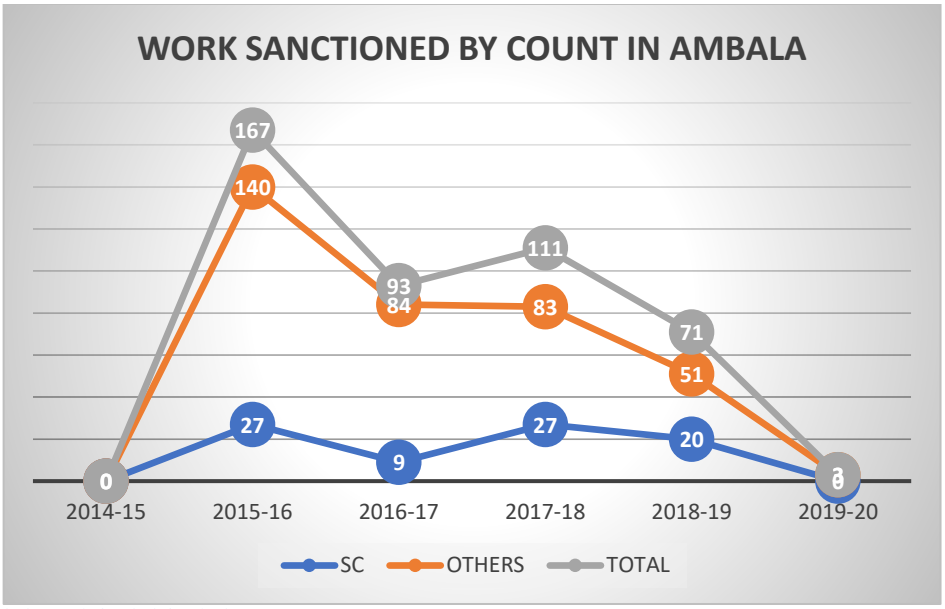

Source: https://mplads.gov.in/mplads/Default.aspx

स्वीकृत कार्य -स्वीकृत कार्यों की संख्या में वृद्धि का रुझान है, स्वीकृत कार्यों की कुल संख्या 2014-15 में 00 से लेकर 2018-19 में 71 तक है, जो पाँच वर्षों की अवधि में पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। परन्तु 2019-20 में कोविड के कारण घट कर 3 तक पहुच गई।

तालिका 7.2: WORK COMPLETED BY COUNT IN AMBALA

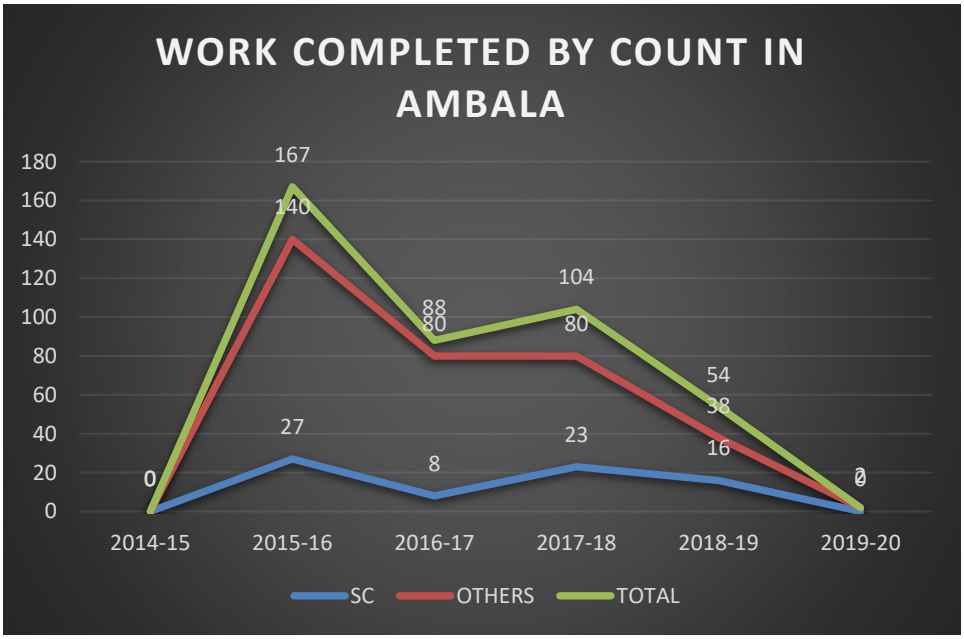

Source: https://mplads.gov.in/mplads/Default.aspx

© 2025 Vaneeta Rani, Dr. Mahinder Singh, Dr. Deepak. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

पूर्ण कार्य - पूर्ण कार्यों की संख्या में उतार चढाव की स्थिति रही, पूर्ण किए गए कार्यों की कुल संख्या 2014-15 में 0 से लेकर 2018-19 में 54 तक पहुच गई, जो विभिन्न वित्तीय वर्षों में परियोजना कार्यान्वयन और पूर्णता को दर्शाता है। परन्तु 2019-20 में कोविड के कारण घट कर 2 तक पहुच गई।

7.2 श्रेणीवार विश्लेषण

7.2.1 अनुसूचित जाति श्रेणी

- 2023 के एमपीएलएडीएस दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है कि संसद सदस्यों (सांसदों) को अनुसूचित जाति (एससी) आबादी वाले क्षेत्रों के लिए कार्यों की सिफारिश करने के लिए अपनी वार्षिक पात्रता का 15 प्रतिशत आवंटित करना चाहिए।
- वित्तीय वर्ष 2014-15 में, कुल 123 कार्यों में से 18 कार्यों की सिफारिश अनुसूचित जाति-बसे हुए क्षेत्रों के लिए की गई थी, जो कुल सिफारिशों का 14.6 है।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 में, कुल 170 कार्यों में से 28 कार्यों की सिफारिश अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए की गई थी, जो कुल अनुशंसित कार्यों का 16.4 था।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए 32 कार्यों की सिफारिश की गई थी, जो उस वर्ष की कुल 168 सिफारिशों का 19.0 था।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में, कुल 147 कार्यों की सिफारिश की गई थी, जिनमें से 43 अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए थे, जो उस वित्तीय वर्ष की कुल सिफारिशों का 29.2 था।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, कुल 108 सिफारिशें की गईं, जिनमें से 32 सिफारिशें अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए थीं, जो उस वित्तीय वर्ष की कुल सिफारिशों का 29.6 थी।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, कुल 3 सिफारिशें की गईं, जिनमें से 1 सिफारिशें अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए थीं, जो उस वित्तीय वर्ष की कुल सिफारिशों का 33.3 थी।
- हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान, अंबाला जिले के कुल 719 कार्यों में से अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए कुल 154 कार्यों की सिफारिश की गई थी, जो कुल सिफारिशों का 21.4 था।

7.2.2 अन्य श्रेणी

- 2014-15 में, कुल 123 कार्यों में से 105 कार्यों की सिफारिश अन्य श्रेणी के लिए की गई थी, जो कुल सिफारिशों का 85.3 है।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 में, कुल 170 कार्यों में से 141 कार्यों की सिफारिश अन्य श्रेणी के लिए की गई थी, जो कुल अनुशंसित कार्यों का 82.9 था।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, अन्य श्रेणी के लिए 136 कार्यों की सिफारिश की गई थी, जो उस वर्ष की कुल 168 सिफारिशों का 80.9 था।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में, कुल 147 कार्यों की सिफारिश की गई थी, जिनमें से 104 अन्य श्रेणी के लिए थे, जो उस वित्तीय वर्ष की कुल सिफारिशों का 70.7 था।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, कुल 108 सिफारिशें की गईं, जिनमें से 76 सिफारिशें अन्य श्रेणी के लिए थीं, जो उस वित्तीय वर्ष की कुल सिफारिशों का 70.3 थी।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, कुल 3 सिफारिशें की गईं, जिनमें से 2 सिफारिशें अन्य श्रेणी के लिए थीं, जो उस वित्तीय वर्ष की कुल सिफारिशों का 66.6 थी।
- हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान अंबाला जिले के अनुशंसित, स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों की कुल संख्या 1579 कार्यों में से अन्य श्रेणी के लिए कुल 1265 कार्यों की सिफारिश की गई थी, जो कुल सिफारिशों का 80.11 था।

तालिका 8: TOTAL WORK BY COST

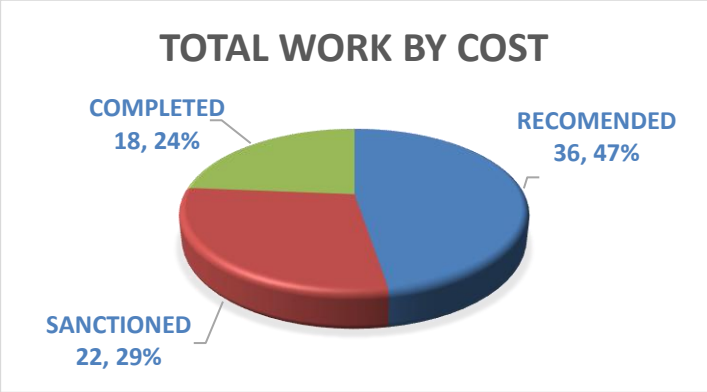

Source: https://mplads.gov.in/mplads/Default.aspx

हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 के कार्यकाल के दौरान अंबाला जिले के अनुशंसित कार्यों की कुल लागत 36 करोड रुपए जो कुल का 47 प्रतिशत थी, स्वीकृत कार्यों की कुल लागत 22 करोड रुपए जो कुल का 29 प्रतिशत थी, और पूर्ण किए गए कार्यों की कुल लागत 18 करोड रुपए जो कुल का 24 प्रतिशत थी।

तालिका 9: TOTAL WORK BY COUNT

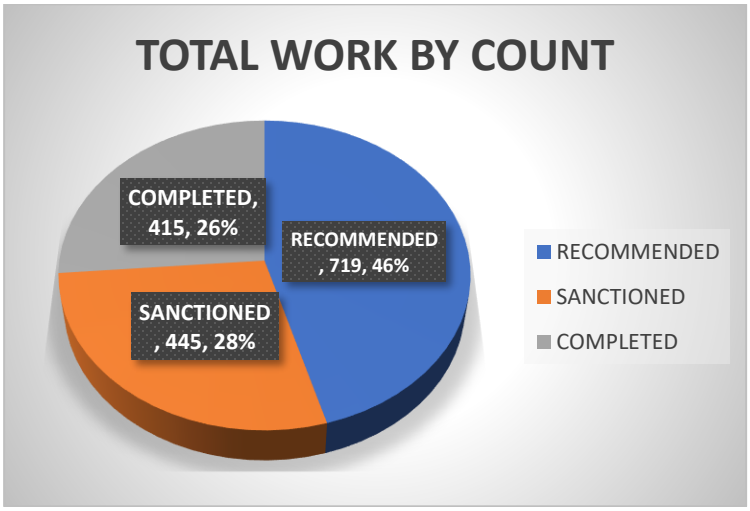

Source: https://mplads.gov.in/mplads/Default.aspx

© 2025 Vaneeta Rani, Dr. Mahinder Singh, Dr. Deepak. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 के कार्यकाल के दौरान अंबाला जिले के अनुशंसित कार्यों की कुल संख्या 719 थी, स्वीकृत कार्यों की कुल संख्या 445 थी, और पूर्ण किए गए कार्यों की कुल संख्या 415 थी।

8. परिणाम

- 6 वर्षों की अवधि में अनुशंसित, स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई, जो स्थानीय विकास पर बढ़ते ध्यान का संकेत है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुशंसित कार्यों की संख्या सबसे अधिक रही, जो तीव्र प्रयासों को दर्शाता है।
- अनुशंसित और स्वीकृत कार्यों की कुल लागत में लगातार वृद्धि देखी गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- पूर्ण किए गए कार्यों पर व्यय में समग्र वृद्धि देखी गई, जो परियोजना कार्यान्वयन में प्रगति का संकेत है।
- अन्य श्रेणी में लगातार सबसे अधिक कार्य दर्ज किए गए, जो एमपीएलएडीएस परियोजनाओं में इसके महत्व को दर्शाता है।
- विभिन्न श्रेणियों में व्यय सालाना बदलता रहा, जिसमें वित्त वर्ष 2018-19 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो स्थानीय विकास के लिए तीव्र प्रयासों का संकेत है।
- हरियाणा में अनुसूचित जाति और अन्य श्रेणियों को आवंटन प्राप्त हुए, जो एमपीएलएडीएस पहलों में उनके महत्व को दर्शाता है।
- विभिन्न श्रेणियों में व्यय में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई, जो स्थानीय विकास परियोजनाओं में निरंतर निवेश को दर्शाता है।
- परन्तु 2019-2020 के वर्ष में कोविड के कारण अनुशंसित और स्वीकृत कार्यों की कुल लागत गिरावट देखी गई

9. सुझाव

परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और नौकरशाही बाधाओं को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसमें अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना, हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाना और कार्यान्वयन एजेंसियों को पर्याप्त सहायता प्रदान करना शामिल हो सकता है। परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने और कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं की पहचान करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को मजबूत करना आवश्यक है। नियमित ऑडिट और मूल्यांकन पारदर्शिता, जवाबदेही और धन के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। परियोजना नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी में अधिक सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने से एमपीएलएडी पहलों की प्रासंगिकता और स्थिरता बढ़ सकती है। सांसदों को प्राथमिकताओं की पहचान करने, संसाधन जुटाने और सेवाओं के प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए। श्रेणियों और क्षेत्रों में संसाधन आवंटन में असमानताओं को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसमें विभिन्न समुदायों की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर धन का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवंटन मानदंडों को संशोधित करना शामिल हो सकता है।सांसदों, कार्यान्वयन एजेंसियों और स्थानीय अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण पहलों में निवेश करने से परियोजना प्रबंधन, बजट और निगरानी में उनके कौशल और क्षमताओं में वृद्धि हो सकती है। प्रासंगिक विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ हितधारकों को एमपीएलएडीएस संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सशक्त बना सकती हैं।

निष्कर्ष

संक्षेप में हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 के कार्यकाल के दौरान अंबाला जिले के अनुशंसित कार्यों की कुल संख्या 719 थी स्वीकृत कार्यों कुल संख्या 445 थी। पूर्ण किए गए कार्यों की कुल 415 थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 के कार्यकाल के दौरान अनुशंसित कार्यों की कुल लागत 36 करोड रुपए थी, स्वीकृत कार्यों लागत 22 करोड रुपए थी,पूर्ण किए गए कार्यों की कुल लागत 18 करोड रुपए थी। एमपीलैड योजना के माध्यम से किए गए विकास कार्यों की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि प्रत्येक जिले में एमपीलैड योजना के तहत आवंटित धनराशि और किए गए कार्यों ने जिले की सभी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इन परियोजनाओं ने विभिन्न अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रमों के पूरक के रूप में योगदान दिया। इनमें से लगभग सभी परियोजनाओं को स्थानीय समुदाय के लोगों की तत्काल आवश्यकताओं पर केंद्रित छोटी परियोजनाओं के रूप में माना जा सकता है। एमपीलैड योजना उन तरीकों में से एक है जिसके द्वारा सांसद और संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लोग मामूली प्रकृति की अत्यंत आवश्यक विकासात्मक आवश्यकताओं की पहचान करने और उन्हें पूरा करने में प्रभावी ढंग से बातचीत करते हैं।

REFERENCES

1. Government of India, Ministry of Statistics and Programme Implementation. Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) Guidelines 2023. Government of India; 2023. Available from: https://mplads.gov.in/mplads/AuthenticatedPages/Reports/Citizen/rptCitizenAssmblyAgencyDetails.aspx
2. Rural Development Department, Government of Haryana. Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS). Government of Haryana; 2025. Available from: https://haryanarural.gov.in/member-of-parliament-local-area-development-scheme/
3. District Ambala, Government of Haryana. About District | District Ambala, Government of Haryana | India.
4. Department of Economic and Statistical Analysis, Government of Haryana. Statistical Abstract of Haryana 2023–24. Government of Haryana; 2025.
5. Government of India, Ministry of Statistics and Programme Implementation. Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) – Official Portal. Available from: https://mplads.gov.in/mplads/Default.aspx
6. Government of India, Ministry of Statistics and Programme Implementation. Members of Parliament Local Area

© 2025 Vaneeta Rani, Dr. Mahinder Singh, Dr. Deepak. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Development Scheme (MPLADS) – Official Portal. Available from: https://mplads.gov.in/mplads/Default.aspx
7. Government of India, Ministry of Statistics and Programme Implementation. Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) – Official Portal. Available from: https://mplads.gov.in/mplads/Default.aspx
8. Government of India, Ministry of Statistics and Programme Implementation. MPLADS Annual Report 2014–15. Available from: https://mplads.gov.in/mplads/AuthenticatedPages/Reports/Citizen/rptCitizenAssmblyAgencyDetails.aspx
9. Government of India, Ministry of Statistics and Programme Implementation. MPLADS Annual Report 2015–16. Available from: https://mplads.gov.in/mplads/AuthenticatedPages/Reports/Citizen/rptCitizenAssmblyAgencyDetails.aspx

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

About the Corresponding Author

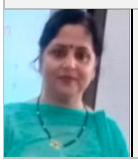

Vaneeta Rani is a research scholar in the Department of Political Science at NIILM University, Kaithal, Haryana, India. Her academic interests include political theory, governance, and contemporary socio-political issues, with a focus on understanding democratic processes and institutional development in India.

© 2025 Vaneeta Rani, Dr. Mahinder Singh, Dr. Deepak. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/